हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद CIN U20299DL 1986NPL023253
EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS
"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070
Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58
Fax: +91-11-26135518 / 19
E-mail: mails@epch.com
Web : www.epch.in

प्रेस विज्ञप्ति

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा केंद्रीय बजट 2023-24 की घोषणा

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाला विकासोन्मुख बजट

नई दिल्ली - 01 फरवरी, **2023**: केंद्रीय बजट 2023-24, श्रीमती निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा 01.02.2023 को संसद में प्रस्तुत किया गया। श्री राकेश कुमार, महानिदेशक-ईपीसीएच ने कहा, बजट का उद्देश्य आर्थिक विकास को सुगम बनाना है और हस्तशिल्प क्षेत्र को लाभ पहुंचाने वाले कुछ उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान (पीएम विकास): हस्तशिल्प कारीगरों की सहायता के लिए एक पैकेज की परिकल्पना की गई है और यह उन्हें एमएसएमई वैल्यू चेन के साथ एकीकृत करते हुए अपने उत्पादों की गुणवत्ता, स्केल और पहुंच में सुधार करने में सक्षम बनाएगा।

• राज्यों को अपने स्वयं के ओडीओपी (एक जिला, एक उत्पाद), जीआई उत्पादों और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों के प्रचार और बिक्री के लिए अपनी राज्य की राजधानी या सबसे प्रमुख पर्यटन केंद्र या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी मॉल स्थापित करने और अन्य सभी राज्यों के ऐसे उत्पादों के स्थान के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

• तांबे के स्क्रैप पर 2.5 प्रतिशत की रियायती मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) भी जारी रखा जा रहा है ताकि द्वितीयक तांबा उत्पादकों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके जो मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में हैं। एचएस कोड 7117 के अंतर्गत वर्गीकृत इमीटेशन ज्वेलरी पर आयात शुल्क 22% या रु. 400/किग्रा, 25% या रु. 600/किग्रा, जो भी अधिक हो, से बढ़ाया जा रहा है ।

• अगले तीन वर्षों के भीतर लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी। युवाओं को अंतरराष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

• व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एक परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) होना आवश्यक है और पैन का उपयोग निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य पहचानकर्ता के रूप में किया जाएगा। इस कदम से निर्यातकों के लिए व्यापार करने में आसानी होगी।

• ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए 39,000 से अधिक कंप्लायंस कम किए गए हैं और 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर-अपराधीकृत किया गया है।

• एमएसएमई क्रेडिट गारंटी - एमएसएमई क्रेडिट की लागत में 1% की कमी। एमएसएमई क्रेडिट के लिए कॉर्पस में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ।

• इंटरेस्ट इक्वलआईसेशन के लिए बजट को 2376 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2932 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

• सरकार ने बंदरगाहों के लिए अंतिम और प्रथम मील कनेक्टिविटी के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की है, और 75,000 करोड़ रुपये (निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित) का निवेश करेगी, और यात्रियों के लिए तटीय शिपिंग को बढ़ावा देगी और माल ढुलाई, पीपीपी मोड के माध्यम से समय और लागत को कम करने में मदद करेगा।

• विवाद से विश्वास ॥: सरकार, वाणिज्यिक विवादों को निपटाने के लिए विवाद से विश्वास-॥ के तहत एक और विवाद समाधान योजना लाएगी जो एमएसएमई और व्यापार को तत्काल आधार पर उनके मुद्दे को हल करने में मदद करेगी।

श्री राज कुमार मल्होत्रा, अध्यक्ष-ईपीसीएच ने कहा, कुछ घोषणाएं हैं जो हस्तशिल्प क्षेत्र को लाभान्वित कर सकती हैं, जिसमें पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान शामिल है, जिसमें कारीगरों के लिए एक पैकेज की परिकल्पना की गई है, जो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में लगे कारीगरों की क्षमता निर्माण में मदद करेगा। एमएसएमई 9000 करोड़ कॉर्पस के निवेश के माध्यम से ऋण की लागत में 1% की कमी जैसी पहल से इस क्षेत्र को मदद मिलेगी।

आगे उन्होंने कहा कि अन्य पहल जैसे हर राज्य की राजधानी में यूनिटी मॉल की स्थापना, ओडीओपी उत्पादों, जीआई उत्पादों और हस्तशिल्प वस्तुओं की बिक्री को बढ़ावा देने से घरेलू बाजार में हस्तशिल्प उत्पादकों के लिए एक विपणन मंच प्रदान करेगा और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 और 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना निश्चित रूप से कौशल विकास की दिशा में की गई पहलों में योगदान देगी।

ईपीसीएच देश से दुनिया के विभिन्न स्थलों के लिए हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प वस्तुओं और सेवाओं की उच्च गुणवत्ता के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में विदेशों में भारत की छवि पेश करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। वर्ष 2021-22 के दौरान हस्तशिल्प निर्यात रु. 33253.00 करोड़ (US $ 4459.76 मिलियन) पिछले वर्ष की तुलना में रुपये के संदर्भ में 29.49% और डॉलर के संदर्भ में 28.90% की वृद्धि दर्ज करते हुए, श्री आर.के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक-ईपीसीएच ने बताया।

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें :
श्री आर.के. वर्मा, कार्यकारी निदेशक - ईपीसीएच
+91-9810697868

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद CIN U20299DL 1986NPL023253

EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

"EPCH HOUSE" POCKET 6 & 7, SECTOR - C, L.S.C., VASANT KUNJ, NEW DELHI-110 070
Tel.: +91-11-26135256 / 57 / 58
Fax: +91-11-26135518 / 19
E-mail: mails@epch.com
Web : www.epch.in

PRESS RELEASE

UNION BUDGET 2023-24 ANNOUNCED BY THE UNION FINANCE MINISTER

- **A GROWTH-ORIENTED BUDGET TO FACILITATE ECONOMIC GROWTH**

New Delhi – 01st February, 2023: The Union Budget for 2023-24 was presented by the Smt. Nirmala Sitaraman, Union Finance Minister in the Parliament on 01.02.2023. Shri Rakesh Kumar, Director General-EPCH said, the budget aims to facilitate economic growth and some of the measures that may benefit handicrafts sector include the following:

- PM Vishwakarma Kaushal Samman (PM VIKAS): A package of assistance for artisans has been conceptualized and will enable them to improve the quality, scale and reach of their products, integrating them with the MSME value chain.

- States will be encouraged to set up a Unity Mall in their state capital or most prominent tourism centre or the financial capital for promotion and sale of their own ODOPs (one district, one product), GI products and other handicraft products, and for providing space for such products of all other States.

- Concessional Basic Custom Duty (BCD) of 2.5 per cent on copper scrap is also being continued to ensure the availability of raw materials for secondary copper producers who are mainly in the MSME sector. Import duty on imitation Jewellery classified under heading 7117 is being increased from 22% or Rs. 400/kg, to 25% or Rs. 600/kg., whichever is higher.

- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 4.0 will be launched to skill lakhs of youth within the next three years. To skill youth for international opportunities, 30 Skill India International Centres will be set up across different States.

- For the business establishments required to have a permanent account number, the PAN will be used as a common identifier for all digital systems of specified government agencies. This step will further help in the ease of doing business for the exporters.

- For enhancing ease of doing business, more than 39,000 compliances have been reduced and more than 3,400 legal provisions have been decriminalized.

- Credit Guarantee for MSMEs - Reducing cost of MSME Credit by 1%. Infusion of Rs. 9,000 crore in corpus for MSME credit.

- Budget for interest subvention has been increased from Rs 2376 cr to Rs 2932 cr up by 23%.

- The announcement that the Government has identified 100 critical transport infrastructure projects, for last and first mile connectivity for ports, and will be undertaking investment of Rs 75,000 crore (incl. Rs 15,000 crore from private sources), and will promote coastal shipping for passengers and freight, through PPP mode shall help reduce logistics time and cost.

- Vivad se Vishwas II: The announcement that the Government will bring another dispute resolution scheme under Vivad Se Vishwas-II to settle commercial disputes will help MSME and trade to resolve their issue on urgent basis.

Shri Raj Kumar Malhotra, Chairman-EPCH said, there are certain announcement that may benefit the handicrafts sector which include PM Vishwakarma Kaushal Samman, wherein a package for Artisan has been conceptualized would certainly help the capacity building of the artisans engaged in the sector. Initiatives like reduction in cost of credit by 1% through infusion of 9000 crore corpus for the MSME would help the sector.

Adding further, he said other initiatives like setting up of unity mall in every state capital thus promoting the sale of ODOP products, GI products and handicraft items would give a marketing platform for the handicraft producers in the domestic market and Prime Minister Kaushal Vikas Yojana 4.0 and setting up of 30 skill India international Centre would certainly add to the initiatives taken towards skill development.

EPCH is a nodal agency for promoting exports of handicrafts from the Country to various destinations of the world and projecting India's image abroad as reliable supplier of high quality of handicrafts goods & services. The Handicrafts exports during the year 2021-22 was Rs. 33253.00 Crores (US $ 4459.76 Million) registering a growth of 29.49% in rupee term & 28.90% in dollar terms over the previous year, informed by Shri R.K. Verma, Executive Director-EPCH.

For more information, please contact:
Shri R.K. Verma, Executive Director – EPCH
+91-9810697868